पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ राज्यपालों का सम्मेलन
राज्यपाल श्री नाईक ने रखा उत्तर प्रदेश का पक्ष
उच्च शिक्षा सहित महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन पर हुई चर्चा
कुलपतियों का कार्यकाल हो पांच साल - श्री नाईक

लखनऊः 6 जून, 2018

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 3 से 5 जून, 2018 को आयोजित तीन दिवसीय 49वें राज्यपाल सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति श्री एम0 वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक सहित अन्य प्रदेशों के राज्यपाल एवं उप राज्यपालों ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर अपने सुझाव रखे। सम्मेलन में राज्य विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा की स्थिति और नियोजनीयता के लिए कौशल विकास, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाए जाने के तौर-तरीकों के बारे में विचार सहित संघ शासित प्रदेशों पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया था।

सम्मेलन के प्रथम दिवस 3 जून, 2018 को राज्यपालों की अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने का राष्ट्रीय निर्णय के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। राज्यपाल श्री राम नाईक ने बैठक में भविष्य में खाद्यान्न की समस्या पर विचार रखते हुये मत्स्य क्षेत्र के विकास पर बल दिया। मत्स्य पालन को विदेशी व्यापार का अच्छा स्रोत बताते हुये उन्होंने स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार का साधन भी बताया। मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों को कृषकों के समान सरकार के स्तर से सुविधायें उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। राज्यपाल श्री नाईक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से अधिक गन्ने का उत्पादन हो रहा है। राज्य में शीरा उद्योग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश भी लाया गया है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है तथा धनराशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा रही है। बैठक में किसानों के विकास से संबंध में गठित की गयी राज्यपालों की एक समिति में श्री नाईक भी सम्मिलित हैं।

सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन 4 जून, 2018 के प्रथम सत्र में केन्द्रीय गृह मंत्री ने स्वागत उद्बोधन देते हुये अनौपचारिक बैठक में हुई चर्चा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अपने विचार रखे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यपालों को सम्बोधित करते हुये देश के विकास तथा उच्च शिक्षा के संबंध में उनके सुझाव मांगे। सम्मेलन के द्वितीय सत्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा0 राजीव कुमार ने जन-केन्द्रित और गरीब उन्मुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों की तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन में अपने विचार रखते हुये राज्यपालों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच सेतु की भूमिका में कार्य करने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश के जनजाति विकास पर बल देते हुये कहा कि देश की आजादी में जनजातियों को विशेष योगदान रहा है। उनके विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने 21 जून को होने वाले योग दिवस पर चर्चा करते हुये कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर योग दिवस का आयोजन किया जाये। योग की महत्ता को देखते हुये पूरे विश्व में योग शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगली बार 50वां स्वर्ण महोत्सव राज्यपाल सम्मेलन होगा अतः बेहतर आयोजन के लिये राज्यपाल सुझाव दें।

राज्यपाल श्री नाईक ने उच्च शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुये गत शैक्षणिक वर्ष में 28 राज्य विश्वविद्यालयों में 15.60 लाख उपाधियाँ वितरित की गयी जिनमें 51 प्रतिशत छात्रायें हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक प्राप्त करने वालों में 66 प्रतिशत लड़कियाँ है। यह महिला सशक्तीकरण का शुभ संकेत है। राज्यपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में अब भारतीय वेशभूषा में ही

दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के समस्त विश्वविद्यालयों को अंग्रेजी दासता की सूचक 'हैट एवं गाउन' को छोड़कर उत्तर प्रदेश में स्थापित इस नई परम्परा का अनुसरण करना चाहिए।

श्री नाईक ने विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल पर चर्चा करते हुये कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपतियों का कार्यकाल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समान पांच वर्ष किया जाना चाहिए जिससे कुलपतिगण विश्वविद्यालय के विकास के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता की दिशा में प्रयास कर सकें। राज्यपाल का मानना है कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के कारण राज्यपाल एक सेतु की भूमिका में कार्य कर सकते हैं इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्यपाल से भी समन्व्य करना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर राज्यपाल का अधिकृत सहयोग लिया जाना चाहिये। राज्यपाल ने संगीत के क्षेत्र में स्थापित देश के एकमात्र भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की भी सिफारिश की। राज्यपाल श्री नाईक ने आई0आई0टी0 बाॅम्बे और मद्रास के नाम मुंबई और चेन्नई का परिवर्तन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये।

सम्मेलन के अंतिम दिन महात्मा गांधी के 150वीं जयंती को भव्य रूप से आयोजित करने के लिये राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यशाला एवं प्रतियोगिता आयोजित करने को सुझाव दिये गये। राज्यपाल श्री राम नाईक इस सत्र के संयोजक थे। उन्होंने 'स्वच्छ भारत अभियान' को जारी रखते हुये और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सबको शौचालय एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को आयोजित करने के लिये प्रदेश स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का उचित सहभाग हो। समारोह के लिये बजट की व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से करने पर भी चर्चा हुई। समारोह के आयोजन के संबंध में अन्य प्रदेश के राज्यपालों ने भी अपने-अपने सुझाव दिये।

अंजुम/ललित/राजभवन (226/3)